सम्पादकीय

रस्मी प्रतिक्रियाओं के अलावा कुछ नहीं

चार दशक पहले बिहार के भागलपुर में कुछ कथित अपराधियों की आंख फोड़ देने की घटना हुई थी। तब समाज में इतनी संवेदना थी कि उसको लेकर कई दिनों तक व्यग्रता जाहिर की जाती रही। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में कहा था कि देश किधर जा रहा है, वो नहीं समझ पा रही हैं। हालांकि तब इस पर कटाक्ष किए गए थे कि अगर ड्राइवर को यह नहीं मालूम की गाड़ी किधर जा रही है, तो उसमें बैठे यात्रियों का क्या हाल होगा! बहरहाल, तब से आज तक हालत बहुत बदल चुकी है। अब ना समाज में वैसी संवेदना है, और राजनेताओं में। इसलिए वैसी ही अमानवीय घटनाएं होती चली जाती हैं और उस पर कुछ रस्मी प्रतिक्रियाओं के अलावा कुछ नहीं होता। अब एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई है। कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश के अलग–अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे मजदूरों को जिले में प्रवेश करने से पहले एक साथ बिठाकर सैनिटाइजर से नहलाया गया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लाजिमी है कि इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंखों में जलन की शिकायत की। लेकिन ऐसी शिकायत के बावजूद किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सभी को जमीन पर बैठाकर उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। बरेली में कोविड–१६ के नोडल अधिकारी अशोक गौतम ने पुष्टि की कि प्रशासन ने प्रवासियों को क्लोरीन और पानी से बने सैनिटाइजर से नहलाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सरकार द्वारा चलाई गई विशेष बसों में आने वाले प्रवासियों की भारी भीड़ के बाद सैनिटाइटरों से प्रवासियों पर छिड़काव करने का सहारा लिया है। यानी ये काम सीधे प्रशासन ने किया। उचित सवाल उठा है कि क्या ऐसा दृश्य किसी हवाई अड्डे पर देखने को मिल सकता था? क्या प्रशासन गरीबों को इनसान नहीं समझता? हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस वीडियो की पड़ताल की गई और प्रभावित लोगों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में उपचार किया जा रहा है। मगर ये सवाल मौजूं हैं कि क्या इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश हैं? केमिकल से हो रही जलन का क्या इलाज है? भीगे लोगों के कपड़े बदलने की क्या व्यवस्था है?

घोषणा में कई बातें दिखावटी

भारत में कोरोना वायरस से फैली अफरा–तफरी के बीच पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के इस राहत पैकेज का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया है। सरकार ने दावा किया कि इसका फोकस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर है। मगर बारीक नजर डालें तो इस घोषणा में कई बातें दिखावटी हैं। मसलन, इसमें ३१ हजार करोड़ रुपए वो भी हैं, जो निर्माण मजदूर कोष में हैं। सरकार पहले ही राज्य सरकारों को उसका उपयोग करने को कह चुकी है। इसी तरह पीएम किसान योजना की २००० रुपए की किस्त वैसे भी किसानों के खाते में जानी थी। उसका कुछ दिन पहले अग्रिम भुगतान कोई अतिरिक्त राहत नहीं है। यही बात मनरेगा मजदूरी में वृद्धि का है, जो मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के साथ पहले से अपेक्षित था। इन सारी रकमों को एक लाख सत्तर हजार में शामिल कर बड़ी राहत का संदेश देना क्या सिर्फ सुर्खियां हासिल करना नहीं माना जाएगा? वैसे ये सच है कि इस पैकेज में घोषित कई उपाय सही दिशा में हैं। जन धन खातों वाली २० करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक ५०० रुपए प्रति माह मिलेगा। ये रकम कम है, फिर भी कुछ ना होने से बेहतर है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले लगभग ८ करोड़ परिवारों को अगले तीन महीनों तक गैस के सिलिंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह एलान भी सही दिशा में है। मगर इसके साथ सप्लाई सुचारू बनाने की बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि देश इस समय ठहराव की हालत में है। तमाम तरह की आपूर्तियां बाधित हैं। एक अन्य उपाय के तौर पर दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत आने वाले महिला स्वयंसेवी समूहों की कोलैटरल मुक्त लोन की सीमा को १० लाख से बढ़ा कर २० लाख कर दिया गया है। इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते इन समूहों के लिए कामकाज की स्थितियां आम दिनों जैसी हों। गरीब और जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्यान्न मिलते हैं, उसके अतिरिक्त अगले तीन महीनों के लिए पांच किलो गेहूं या चावल मिलेगा। उन्हें इस अवधि में हर महीने एक किलो दाल भी निशुल्क मिलेगी। हालांकि इसमें भी पेच है और आपूर्ति का सवाल है। इसलिए फिलहाल, यही कहा जा सकता है कि सरकार ने सही दिशा में सोचा है, मगर वह बहुत साहसी सोच नहीं दिखा पाई है।

सरकारों के सामने भरोसे का संकट

अजीत कुमार

लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के अपने अस्थायी प्रवास से निकल कर अपने गांव–घर पहुंचने की जद्दोजहद ने केंद्र और राज्यों की सरकारों के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि पहला बड़ा संकट आते ही लोग अपने घर की ओर भागने लगे? यह सही है कि संकट के समय में सबको अपना घर और अपने लोग याद आते हैं। क्योंकि किसी भी संकट के समय इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और उस समय उसको उसी स्तर की संवेदना और सहारे की जरूरत होती है। कोरोना वायरस के संकट के समय में भी सेहत और आर्थिक स्थिति की चिंता ने लोगों को भावनात्मक रूप से कमजोर किया और अफसोस की बात है कि उनका परिवेश और सरकार दोनों उन्हें इस भावनात्मक कमजोरी से उबरने के लिए जरूरी सहारा देने में सफल नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि प्रवासी मजदूरों ने सरकारों पर भरोसा क्यों नहीं किया? जब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग घरों में रहें और अगले २१ दिन यह भूल जाएं कि 'घर से निकलना क्या होता है' तो लोगों ने इसे माना क्यों नहीं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी आदमी को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ध्यान रहे उनके यह घोषणा करने के दो दिन के बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लाख ७० हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने जन धन खातों में हर महीने पांच सौ रुपए डालने का ऐलान किया और मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की। इस बीच अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ऐलान किया कि वे हर दिन चार लाख लोगों को दो वक्त का भोजन मुहैया कराने जा रहे हैं। इसके लिए आठ सौ से ज्यादा सेंटर बनाने की घोषणा हुई। उन्होंने प्रति दिन एक हजार कोरोना संक्रमितों की संभावना के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी की। केजरीवाल सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य के मामले में उनके जैसा काम देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इसका मतलब है कि देश के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है। सो, कायदे से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद लोगों को इसके बाद अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए था। पर लोग इस घोषणा के बीच ही घरों से निकलने लगे और पैदल ही अपने गांव की ओर कूच कर गए। उन्होंने न केंद्र सरकार की घोषणा पर भरोसा किया, न उसके पैकेज से कोई उम्मीद पाली और न दिल्ली सरकार की घोषणा व उसकी स्वास्थ्य सेवा पर भरोसा

किया। यहां केंद्र और दिल्ली सरकार का जिक्र प्रतीक के तौर पर हो रहा है। लोगों ने हरियाणा सरकार पर भी भरोसा नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार की अपील भी नहीं मानी, न गुजरात सरकार की एक सुनी और न केरल सरकार की बात मानी। देश के जिन राज्यों में भी औसत से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का अनुपात है वहां से पलायन हुआ। इसका सीधा कारण यह समझ में आता है कि सरकारों ने अपना भरोसा गंवा दिया है। यह कोई पांच या दस साल में हुई परिघटना नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही संकट के समय सरकारों की प्रतिक्रिया से आम लोगों के मन में यह धारणा बनी है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं। सबको खुद ही अपने आप को संभालना होता है और बचाना होता है। प्रवासी मजदूरों के पलायन से तो यह जाहिर हुआ है कि सोशल मीडिया के संदेशों में भी इसकी झलक मिल रही है। हर किस्म के सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों के व्हाट्सएप समूहों में यह मैसेज घूम रहा है कि कोई सरकार बचाने नहीं आएगी, सबको खुद ही बचना है और एक–दूसरे की मदद करनी है। वैसे भी संकट के समय भारत के लोगों में 'जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए' या 'होइहें वहीं जे राम रचि राखा' की भावना मजबूत होती है। सो, कोरोना वायरस के संकट के समय भी लोग सरकारों से ज्यादा भगवान के भरोसे हैं। अगर मजदूरों ने पलायन किया तो उन्होंने इसे अपनी नियति मान कर ऐसा किया। इस दौरान अगर दर्जनों लोगों की मौत हो गई तो उसे भी नियति का खेल माना गया। दुनिया के हर सभ्य समाज में लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि सरकार कह रही है कि वह संकट नहीं बढ़ने देगी या संकट के समय अपने नागरिकों की मदद करेगी तो वह ऐसा करेगी। पर भारत में नागरिक पहले से यह मानते हैं कि सरकारें जो कह रही हैं वह नहीं करेंगी। सबको अपनी व्यवस्था खुद ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि यह भावना सिर्फ पलायन करने वाले मजदूरों में दिखी है। जिन लोगों ने पलायन नहीं किया उनके मन में भी यहीं धारणा है कि उन्हें खुद ही अपने को बचाना है। यह भी सुनने को मिला कि जब डक्टर और नर्सें खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो वे मरीजों को कैसे बचाएंगे? सोशल मीडिया के प्रसार ने लोगों को भटकाया है तो कई मामलों में जागरूक भी बनाया है। उनको दिख रहा है कि सरकार के प्रयास हवा में तीर मारने जैसे हैं। सरकार भी भगवान भरोसे बैठी है कि शायद सबको घरों में बंद कर देने से संक्रमण रुक जाए या मौसम में गरमी बढ़े तो वायरस खुद ही मर जाए या दुनिया के देश कोई दवा ही खोज लें तो इसका मुकाबला हो जाए। याद करें कैसे पिछले साल बिहार में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे और सरकार इस इंतजार में बैठी थी बारिश हो जाए तो बीमारी खत्म हो। और ऐसा ही हुआ भी। बारिश शुरू हुई और बच्चों के मरने का सिलसिला बंद हो गया और फिर सरकार का काम पुराने ढर्रे पर चलने लगा। ऐसी अनगिनत घटनाओं से लोगों के मन में सरकारों के प्रति अविश्वास बना है। इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है।

रामलला को टैंट से मुक्ति

राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों की बात करें तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है और इस महामारी के चलते विश्व भर में अब तक २६ हजार लोगों की मौत हो चुकी है। जान माल के नुकसान की हानि विश्व युद्धों में भी नहीं हुई जितनी इस अदृश्य वायरस के कारण हो रही है। एक तरफ मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ विश्वभर की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आती जा रही है और दुनिया मंदी की गिरफ्त में आ गयी है। दुनिया भर के नेता इस संकट से निबटने के उपायों पर मंथन कर रहे हैं चाहे वाह जी–२० की बैठक हो, सार्क की बैठक हो या अन्य वैश्विक मंच। सभी का प्रयास है कि इस महामारी से एकजुट होकर निपटा जाये। अभी देखना होगा कि यह वायरस मानवता पर और कितना कहर बरपाता है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते आजाद भारत को पहली बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया जहां ना ट्रेन चल रही है, ना प्लेन, जहां ना मेट्रो चल रही है ना बस, सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों की गति पर ब्रेक लगा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद होकर गिन–गिन कर दिन काट रहे हैं ताकि २१ दिन का यह लॉकडाउन सफल हो जाये और इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। सरकार भी लोगों को राहत पहुँचाने के सभी प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है तो आरबीआई ने सभी प्रकार के लोन सस्ते करने का इंतजाम कर दिया है और बैंकों को यह छूट प्रदान कर दी है कि वह अपने ग्राहकों को ईएमआई के भुगतान में तीन महीने की राहत दे सकें। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी–अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं कि जनता को हर तरह से राहत प्रदान की जा सके। इस सप्ताह के अन्य बड़े मुद्दों की बात करें तो संसद का बजट सत्र समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान आम बजट को पारित करा लिया गया। मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान आ गये क्योंकि कांग्रेस के बागी विधायकों के कारण कमलनाथ सत्ता से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा अयोध्या में रामलला को टैंट से मुक्ति मिली और उन्हें फाइबर से बने अस्थाई मंदिर में स्थापित किया गया जहाँ वह भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने तक विराजमान रहेंगे।

कोरोना महामारी का सबक

विवेक सक्सेना

कोरोना वायरस से फैली महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा गंभीरता से उठा है। इस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। भारत के लिए भी ये बहस अहम है, क्योंकि अपने यहां इनकी हालत और भी लचर है। इस मुद्दे से जुड़ा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इस महामारी के कारण अलग–अलग देशों में पीड़ित लोगों के बीच मौतों की दर अलग–अलग क्यों रही है। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे अहम सवाल यह है कि किसी देश की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना वायरस जैसी किसी महामारी का सामना करने के लिए कितनी तैयार हैं। साथ ही यह भी कि क्या वो संक्रमण की गति को रोकने में सक्षम हैं। गति रोकने का मतलब है कि कि क्या संक्रमण और मृत्यु दर को पूरी आबादी में रोग के फैलने के बाद भी स्थिर रखा जा सकता है। अनुभव यह है कि ऐसा करना संभव है, बशर्ते स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हों। मसलन, कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर मशीनों के सहारे मरने से रोका जा सकता है। जरूरी यह है कि पर्याप्त संख्या में जरूरी उपकरणों से लैस अस्पताल, बेड और मशीनें मौजूद हों। अगर बहुत कम इंटेंसिव केयर बेड और वेंटीलेटर होंगे, तो जिन मरीजों को इनकी सुविधा नहीं मिलेगी, उनके मरने का खतरा ज्यादा होगा। इस मामले में जर्मनी और इटली की तुलना उपयोगी है। इटली की आबादी छह करोड़ है। महामारी जब शुरू हुई, तो वहां इंटेंसिव केयर के ५००० बेड मौजूद थे। जर्मनी में आठ करोड़ आबादी है। यहां २८,००० इंटेंसिव केयर बेड हैं। खबर है कि जर्मनी बहुत जल्द अपने इंटेंसिव केयर बेड की संख्या दोगुनी कर लेगा। जर्मनी में प्रति एक लाख लोगों पर २६ बेड हैं। जबकि इटली में केवल १२ और स्पेन में प्रति एक लाख लोगों पर केवल १० इंटेंसिव केयर बेड हैं। यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर टेस्ट और मरीजों को अलग–थलग रखने की व्यवस्था के जरिए कोविड–१६ को फैलने से रोका है। दक्षिण कोरिया ने लोगों को क्वारंटीन करने के लिए सख्त नियम बनाए और शुरूआत से ही संक्रमण की गति को एक समान बनाए रखा। इस देश में महज १० हजार लोग संक्रमित हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि महामारियां मौत की सिर्फ एक वजह होती हैं। इसकी दूसरी वजह स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव होता है। हम चाहें तो इससे जरूरी सबक ले सकते हैं।

दुख में सुमिरन सब करे.....

अंजू निगम देहरादून

कुछ दिनो पहले मेरी दोस्त की वॉल पर एक पोस्ट चमकी। सीमित संसाधनो का प्रयोग करे ताकि आपको घर के बाहर ज्यादा न निकलना पड़े। पढ़ कर सोच को सकारात्मक दिशा मिली और उसे अमल में लाना भी शुरू किया। नतीजे बेहतर रहे। दूनिया आज जब इस भीषण त्रासदी के बीच झुल रही है, जहाँ सभ्यता ही विनाश के मुहाने पर खड़ी हैद्य और कई छोटे देश जिनकी सीमित जनसंख्या है, इस जानलेवा वाइरस की सबसे ज्यादा चपेटे में है, ऐसी ही सकारात्मकता की जरूरत है। पर इंसानी सोच कहे या फितरत वो हर बात का नकारात्मक पहलू भी ढुढँ ही निकालते है। आज जब दूनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश भी इस महामारी से आक्रांत है, हमने पूरी ताकत से इस वाइरस को वृहद बनने से रोक रखा है और अगर आंकड़े ये दिखा रहे हैं तो इसे बनाये रखने के लिए हमे धार्मिक विवादो से विलग होकर इस पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। अगर हम इस मानसिकता से नहीं निकल पाये तो इस कठिन दौर में ये सोच हमे किस मोड़ तक ले जायेगी, इसका कयास भर लगाया जा सकता है। ये भी सच है कि हर उन विषमताओं से हमने बाहर निकलना सीखा हैं जो हमे गर्त की ओर धकेलती है। हमारी एकजूटता इसकी मिसाल बनी है। फिर चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर २२ मार्च का जनता कर्फ्यू हो,या उसी शाम पाँच बजे शंख, थाली बजा स्वास्थ्य सेवा में जूटे फरिश्तो का सादर आभार करने का मौका हो। लोगो ने अपने

विशाल हृदय का परिचय दिया है। कई तरफ से ऐसी बानगी भी देखने को मिल रही है जिससे ये विश्वास पुख्ता होता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। दिहाड़ी पर काम करने वाले, उन लघुकारखानो में काम करने वाले(जो लॉकडाउन से तकरीबन ठप्प पड़ गये है) जो खाने तक के लिए मोहताज बन गये है। ऐसे लोगो की मदद के लिए जगह जगह लंगर लगने लगे है ताकि कोई भुखा न रहे। सरकार तो मदद कर रही है पर उससे पहले खुद हमे अपनी और आस पास के जरुरत मंद लोगो को मदद के दायरे में लाना होगा और ऐसा हो भी रहा हैद्य मानवता के कई पहलू अलग अलग रूपो में सामने आ रहे हैं। डाक्टर–नर्स, केमिस्ट, जरूरी सामानो के दुकानदार से लेकर सब्जीवाले, सफाई कर्मचारी अपना अपना योगदान दे रहे है। उस दिन पढ़ा कि अपनी जान की परवाह न करता सब्जी वाला जरूरत मंदो के यहाँ सब्जी पहुँचा रहा था। डाक्टर ने मास्क खत्म हो जाने पर एक सफाई कर्मी को अपने लिए रखा मास्क दे दिया। एक अखबार ने अपना एक ट्विटर अंकाउट खोला है, जिसमें ऐसे फरिश्तो द्वारा बढाये गये हाथो के अनगिनत किस्से संकलित हो रहे है। बॉलीवुड के कई दिग्गजो ने मदद के हाथ बढ़ाये है। इस विश्व व्यापी आपदा ने खत्म हो रही मनुष्यता को मानवता का एक नया पाठ पढाया है, एक नये पायदान पर बिठाया है। फिर अपवाद तो हर जगह है। उसे बिसार हम उजालो की एक नयी, स्वस्थ दूनिया का निर्माण तो कर ही सकते है। जरूरत फौलादी इरादो और मजबूत सकारात्मक विचारो का है।